शाखाओं के माध्यम से जब प्रोजेक्ट मानकों के आधार पर प्रस्तुत होता है, वह approve होता है, उसके बाद उसको क्रियान्वयन की दृष्टि से हम लोग लाते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से सदन को यह भी अवगत कराना चाहती हूँ कि Empowered Committee के पास आदेश यह है कि हम हर दो-तीन महीने में मिलें। मेरा प्रयास रहेगा, मैं वित्त मंत्री से आग्रह करूंगी कि Empowered Committee हर महीने मिले, ताकि हम प्रयत्नशील हों कि financial and physical progress of projects के ऊपर भी हम लोग ध्यान दे सकें।

नीति घाटी में सम्पर्क संबंधी समस्या

*273. **श्री पी.एल. पुनिया**: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि भारत-चीन सीमा पर स्थित नीति घाटी के ग्यारह गांवों का संपर्क विगत दो माह से कटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त गांवों के साथ-साथ भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, सेना और सीमा सड़क संगठन की चौकियों में भी संचार सेवा पूर्णतया ठप्प पड़ी हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) उपग्रह में आई तकनीकी खामियों को दो महीनों के बाद भी ठीक नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

संचार, विधि और न्याय तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) भारत चीन सीमा के पास स्थित नीति घाटी के गांवो में सभी डिजिटल सेटेलाइट फोन टर्मिनल (डीएसपीटी) बाधित हुए हैं।

डिजिटल सेटेलाइट फोन टर्मिनल (डीएसपीटी) के माध्यम से संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (आईएसआरओ) की अनुषंगी कंपनी मैसर्स अंतरिक्ष से एनएसएस-6 उपग्रह (गैर-स्वदेशी उपग्रह) पर लगभग 25 मेगाहट्र्स बैंडबिड्थ का प्रापण किया था। सुरक्षा चिंता का उल्लेख करते हुए मैसर्स अंतरिक्ष ने बीएसएनएल से डीएसटीपी सेवाओं को एनएसएस-6 सेटेलाइट से जीएसएटी-18 सेटेलाइट (स्वदेशी उपग्रह) पर अंतरित करने का बारंबार आग्रह किया। हांलाकि बीएसएनएल ने मैसर्स अंतरिक्ष से डीएसटीपी सेवाओं को एनएसएस-6 उपग्रह से जारी रखने का अनुरोध किया था क्योंकि इन सेवाओं को अंतरित करने में एंटीना का पुनः ओरियंटेशन करने/एंटीना मांउट को पुनः स्थापित करने आदि जैसे अनेक कार्यकलाप शामिल थे। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के अंतरण कार्यकलापों में अत्यधिक व्यय भी निहित था।

मैसर्स अंतरिक्ष ने दिनांक 13.05.2019 को एनएसएस-6 उपग्रह के ट्रांसपोंडर को यह उल्लेख करते हए बंद कर दिया कि उपग्रह की कार्य अवधि पहले ही पूर्ण हो चुकी हैं। इसकी वजह से दिनांक 13.05.2019 से डीएसटीपी सेवाएं बंद हो गईं।

उपर्युक्त कारणों से भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), सेना और सीमा सड़क संगठन के आउटपोस्ट में डीएसटीपी के माध्यम से प्रदान की जा रहीं संचार सेवाएं भी बाधित हुईं।

तथापि, फिलहाल प्रचालनात्मक संचार के लिए सीमावर्ती आउट पोस्ट (बीओपी) पर आई-सैट फोन उपलब्ध हैं।

बीएसएनएल ने दूरसंचार विभाग (डीओटी)/सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) को डीएसटीपी सेवाओं के बंद होने के कारणों से अवगत करा दिया है और प्रत्येक स्थान पर एंटीना का पुनः आरियंटेशन करने, जहां कहीं भी आवश्यक हो एंटीना को पुनः स्थापित करने से संबंधित अंतरण कार्यकलाप जो समय लगने वाला (20 से 25 सप्ताह) कार्य है और जिसमें पर्याप्त लागत शामिल है, के लिए वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है।

इन क्षेत्रा में सेवाओं को शीघ्र बहाल करने के लिए दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने का वाम संभावनाओं की तलाश की जा रही है।

Connectivity issue in Niti Valley

†273. SHRI P. L. PUNIA: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that eleven villages of Niti Valley located along Indo-China border are disconnected for the last two months;

(b) if so, the details thereof alongwith the reasons therefor;

(c) whether it is also a fact that the communication service in the outposts of Indo-Tibetan Border Police (ITBP), Army and Border Roads Organisation along with the villages is also completely disrupted and if so, the details thereof; and

(d) the reasons for not fixing the technical faults in the satellite even after two months?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (d) Sir. All the Digital Satellite Phone Terminals (DSPTs) have been disrupted in the villages of Niti valley located along Indo-China border.

For providing communication service through Digital Satellite Phone Terminals (DSPT), approximately 25 MHz bandwidth on NSS-6 Satellite (non-indigenous satellite) was procured by Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) from M/s Antrix,

† Original notice of the question was received in Hindi.

a subsidiary of Indian Space Research Organization (ISRO). Citing the security concern, M/s Antrix repeatedly asked BSNL to migrate DSPT services from NSS-6 Satellite to GSAT-18 Satellite (indigenous satellite). However, BSNL requested M/s Antrix to continue the DSPT services on NSS-6 Satellite as a lot of activities such as re-orientation of antenna/relocation of antenna mount etc. were involved. Moreover, a huge expenditure was also involved in various migration activities.

M/s Antrix w.e.f. 13-05-2019 turned off the transponder of NSS-6 Satellite stating that the said Satellite has already completed its life. Due to this, the DSPT services got discontinued w.e.f. 13-05-2019 onwards.

The communication services provided through DSPTs are also disrupted in the outposts of Indo-Tibetan Border Police (ITBP), Army and Border Roads Organisation for the reasons detailed above.

However, at present I-SAT Phones are available at Border Out Posts (BOPs) for operational communication.

BSNL appraised the reason for discontinuation of DSPT services to Department of Telecommunications (DoT)/Universal Service Obligation Fund (USOF) requesting financial support in carrying out the migration activity which is a time taking activity (20-25 weeks) for re-orientation of antenna at each location, relocation of antennas wherever needed and also involve substantial cost.

Various possibilities of providing telecom services in these areas are being explored for early restoration of services.

श्री पी. एल. पुनिया: मान्यवर, भारत-चीन सीमा पर नीति घाटी के सभी गांवों में दूरसंचार व्यवस्था 13 मई, 2019 से ठप है, जिससे आम नागरिक के अलावा आईटीबीपी, आर्मी, बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन की आउटपोस्ट्स पूर्णतः प्रभावित हैं। माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में यह स्वीकार किया है।

सीमा पर इस प्रकार देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही। यह सब अचानक नहीं हुआ। BSNL को इसरो की सहायक कम्पनी "अंतरिक्ष" द्वारा निरंतर कहा जा रहा था कि वह इन सेवाओं को NSS-6 सैटेलाइट से GSAT-18 सैटेलाइट में शिफ्ट करा ले, लेकिन BSNL ने कोई कदम नहीं उठाया और 13.05.2019 को NSS-6 सैटेलाइट तथा संचार सेवाएँ बन्द हो गयीं।

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि इस गम्भीर लापरवाही के लिए किन-किन अधिकारियों के खिलाफ क्या-क्या कार्रवाई हुई है?

श्री रविशंकर प्रसाद: महोदय, एक बात समझने की आवश्यकता है कि जो सीमा क्षेत्र पर आउटपोस्ट्स हैं, वे हमारी सेना के हैं, बीएसएफ के हैं, आईटीबीपी के हैं और चूंकि वे ऊँचाई पर हैं और दूरी पर हैं, तो हम उनको सैटेलाइट फोन की सुविधा देते हैं। सैटेलाइट फोन एक

सैटेलाइट से ही कनेक्टेड रहता है। तो जैसा माननीय सदस्य ने बताया कि जो NSS-6 सैटेलाइट था, उसके बारे में यह कहा जा रहा था कि आप इससे अलग होइए। अब कठिनाई यह थी कि दूसरे सैटेलाइट से reconfiguration करने के लिए, एक-एक सिस्टम को उसके अनुसार पहाड़ों में ठीक करने के लिए लगभग 10 माह से 1 साल का समय लगता है और खर्चा भी बहुत होता है। इस विषय को मैंने कल स्वयं देखा है। माननीय सदस्य की चिन्ता बहुत वाजिब है कि हमें सीमांत क्षेत्रों में सैनिकों और जनता का सम्मान करना चाहिए। ...**(व्यवधान)**... मैंने फैसला किया है कि जो हमारे ऐसे 496 एमएचए एजेंसियों के महत्वपूर्ण स्थान हैं, जिसमें नीति वैली के गांव भी शामिल हैं, उन्हें तुरन्त आईसेट (सैटेलाइट) से लिंक किया जाएगा और वहां यह सुविधा दी जाएगी।

श्री पी. एल. पुनिया: धन्यवाद मंत्री जी। 13 मई से भारत-चीन सीमा पर दूरसंचार सेवा ठप है। देश में अन्य जगहों पर भी DSPT सेवाएं ठप होंगी। मंत्री जी ने जवाब में उल्लेख किया है कि बी.एस.एन.एल. ने आर्थिक सहायता के लिए Department of Telecommunications और Universal Service Obligation Fund से अनुरोध किया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ITBP, Army, Border Roads Organization के अलावा आम पब्लिक को दूरसंचार सुविधाओं की पूर्णतया बहाली के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है और कितने समय में वैकल्पिक व्यवस्था पूरी कर ली जाएगी?

श्री रवि शंकर प्रसाद: मैं माननीय सदस्य को बहुत विनम्रता से बताना चाहूंगा कि सीमा क्षेत्रों में जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज़ एण्ड पैरा-मिलिटरी फोर्सेज़ हैं, उनके personnel को एक रुपए में हम यह सुविधा देते हैं, जबकि एक सैटेलाइट फोन पर normally 25 रुपए प्रति मिनट लगता है। इसे हम subsidize करते हैं। यह हमारी चिन्ता है और होनी भी चाहिए। अपने सैनिकों के प्रति हमारा यह obligation है और हमें करना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि नीति घाटी में सिर्फ 27 गांव हैं। अभी मैंने जो घोषणा की, कुल 496 एमएचए एजेंसियों के महत्वपूर्ण स्थान की हम चिन्ता कर रहे हैं और उन्हें आईसेट से जोड़ रहे हैं। इसलिए माननीय सदस्य ने जो चिन्ता जताई है, उसका भी इसमें समाधान हो जाएगा। हम इस ओर पूरा ध्यान दे रहे हैं।

श्री अनिल बलूनीः महोदय, मैं माननीय मंत्री जी की जानकारी में लाना चाहता हूं कि उत्तराखंड में उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ ऐसे जिले हैं, जो अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं। वहां बड़ी संख्या में गांव हैं लेकिन उस क्षेत्र में मोबाइल सेवा आज बड़ी खस्ता हालत में है। बहुत बड़ी संख्या में वहां मोबाइल टॉवर लगाने की आवश्यकता है। बॉर्डर क्षेत्र होने के कारण, वहां कोई दूसरा communication का साधन भी नहीं है। जो private operators हैं, वे भी वहां operate करने में ज्यादा इच्छुक नहीं लगते। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आप सीधे सवाल पर आइए। ...**(व्यवधान)**...

श्री अनिल बलूनी: मेरा सवाल है कि उस क्षेत्र में दूरसंचार सेवाओं को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्री रवि शंकर प्रसाद: महोदय, बलूनी जी पहाड़ों से आते हैं। उनकी चिन्ता पहाड़ों के प्रति है, इसे मैं जानता हूं। मैं स्वयं उत्तराखंड का प्रभारी रहा हूं और मैंने उनके काम को भी देखा

है। यहां हम एक बात को समझें और इस सदन को भी बताना ज़रूरी है कि तमाम कमजोरियों के बावजूद वहां सारे काम BSNL ही करता है, जो border areas में होते हैं। वहां तूफान आता है, बाढ़ आती है, भूकम्प आते हैं – ऐसे समय ये ही फ्री सेवाएं देते हैं, इसे सदन को समझना बहुत जरूरी है। इसके साथ-साथ उन्हें कम्पीटशन भी करना पड़ता है। माननीय सदस्य ने specific उत्तर काशी और बागेश्वर आदि की बात कही है, इस समय वहां क्या-क्या काम चल रहे हैं, जरूर कुछ कमी रही होगी, उसकी अद्यतन स्थिति मालूम करके मैं उन्हें बता दूंगा।

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: You are aware that Andhra Pradesh is frequently struck with cyclones and all that. I would like to ask the Hon'ble Minister one thing. Do we have any institutional mechanism to restore the telecommunications in disaster-affected areas to save the valuable human lives and livestock? Unless the communications are restored instantaneously, this is not possible. So, my question is: Do we have any institutional mechanism in place or not?

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Hon'ble Member would appreciate that this question relates to a specific area of Niti Valley, high in the hills of Uttarakhand. Since he has raised this issue, I only wish to inform him, and many of the senior Hon'ble Members would know it, whenever any natural disaster strikes, there is a proper protocol or Standard Operating Procedure whereby NDRF, SDRF and all cooperate and we take steps so that free mobile phone connectivity is available. It is restored and there is a Standard Operating Procedure for it. If he asks me any specific question about any specific area of Andhra Pradesh, I will separately furnish the details.

श्री प्रदीप टम्टा: उपसभापति महोदय, पुनिया जी ने अभी नीति घाटी और चमोली क्षेत्र के बारे में सवाल किया। हमारे क्षेत्र में, जैसा कि अनिल जी ने भी बताया, पिथौरागढ़ है, वह सीमांत का जिला है, धारचूला तहसील और मुनस्यारी तहसील के लोग लंबे समय से मोबाइल नेटवर्क की मांग भी कर रहे हैं, इसके लिए आंदोलनरत भी हैं। यह एकदम सीमा से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, आईटीबीपी और हमारी आर्मी भी वहां पर है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या एमटीएनएल या बीएसएनएल के नेटवर्क को बढ़ाने के लिए सरकार कोई कार्रवाई कर रही है? 2013 की आपदा के बाद वहां पर आपदा के समय कुछ doppler radar लगाने की बात हुई थी, उस पर आगे कोई बात नहीं बढ़ी है। क्या वहां पर मोबाइल के नेटवर्क को लोगों की सेवाओं के लिए, जो खुद विभाग के पास प्रस्ताव है उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे? ...**(व्यवधान)**... सीमांत के लोगों के लिए, पिथौरागढ़ जिले के धारचूला और उन्स्याबी तहसील के जो प्रस्ताव हैं कि वहां मोबाइल नेटवर्क के क्षेत्र को बढ़ाया जाए, उस पर सरकार विचार करेगी या नहीं करेगी? ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: इस तरह हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए कृपया सवाल बहुत specific करें।

श्री रवि शंकर प्रसाद: महोदय, मैं उस इलाके के बारे में तथ्य जुटा कर माननीय सांसद जी को बता दूंगा।

Performance of BSNL

*274. SHRI RONALD SAPA TLAU: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that 54,000 BSNL employees are in danger of losing their jobs and if so, the reasons therefor;

(b) if not, the present status of BSNL in terms of effective performance and competitiveness;

(c) whether any survey has been done/approved by Government, to identify the overall performance of BSNL in comparison to other competing companies; and

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI DHOTRE SANJAY SHAMRAO): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) has informed that no proposal to lay off over 54,000 employees has been approved by BSNL.

(b) As informed by BSNL, as per TRAI report the total market share of BSNL is as follows:—

Market Share in terms of subscribers (in %age)

BSNL	As on 31.03.2017	As on 31.03.2018	As on 31.03.2019
Wireless (Mobile)	8.66	9.44	9.96
Wireline	56.15	53.78	51.47
TOTAL	9.63	10.26	10.72

However, stiff competition in mobile segment, high employee cost and absence of 4G services (except in few places for BSNL) in the data-centric telecom market is adversely affecting the competitive strength of BSNL.

(c) and (d) No survey has been done/approved by the Department of Telecommunications (DoT) to identify the overall performance of the BSNL in comparison to other competing companies.